Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.shisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2024 SHISRRJ | Volume 7 | Issue 6
ISSN : 2581-6306
doi : https://doi.org/10.32628/SHISRRJ

भारत में सार्वजनिक नीतियों की दिशा: सरकार की भूमिका और नागरिक सहभागिता

डॉ0 सुधांशु चौबे
सहायक प्राध्यापक, प्रवासी अध्ययन केंद्र, (स्वतंत्र केंद्र) गुजरात केंद्रीय विश्वविधालय, गुजरात, भारत।
डॉ0 गजेन्द्र
सहायक प्राध्यापक, प्रवासी अध्ययन केंद्र, (स्वतंत्र केंद्र) गुजरात केंद्रीय विश्वविधालय, गुजरात, भारत एवमं पोस्ट-डॉक्टरल फेलो, आई सी एस एस आर, नयी दिल्ली।

Article Info

Accepted : 05 Nov 2024
Published : 25 Nov 2024

Publication Issue :
November-December -2024
Volume 7, Issue 6

Page Number : 27-35

सारांस - भारत की सार्वजनिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे है। तकनीकीकरण, तमाम सामाजिक और राजनितिक बदलाव, डिजिटल गवेर्नेंस का उदय, परिणाम उन्मुख शासन व्यवस्था आदि कुछ ऐसे कारक है जिनके कारण ये परिवर्तन हो रहे है। भारत में विकेंद्रीकरण और सहभागी शासन पर अब अधिक जोर दिया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार तकनीक का इस्तेमाल करके डिजिटल गवर्नेंस का एक सफल उदाहरण पेश कर रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर जैसी सहभागी परियोजनाओं का प्रयोग करके वर्तमान सरकार ने शासन को सहभागी बनाया है। विश्व के मानक स्तरों पर भी भारत की नीतिया खरी उतर रही है। यह शोध पेपर इन्ही सार्वजनिक नीतियों का एक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों की एतिहासिक यात्रा का वर्णन करना तथा उनमे होने वाले मौलिक परिवर्तनों का अध्ययन है। इसमें सरकार की भूमिका और नागरिक सहभागिता को कैसे बढाया जा सकता है यह जानने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द- सार्वजनिक नीतिया, मोदी सरकार, नागरिक सहभागिता, न्याय।

प्रस्तावना - हाल के दशकों में भारत के सार्वजनिक नीति परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तकनीकी प्रगति, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक एकीकरण से प्रेरित होकर भारत आर्थिक विकास को सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। भारत में सार्वजनिक नीतियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है जो तकनीकी प्रगति तथा सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्यों में बदलाव और वैश्विक आर्थिक एकीकरण से प्रेरित है। ये बदलाव बढती असमानता, जलवायु परिवर्तन और संसाधन प्रबंधन जैसी समकालीन चुनौतियों का समाधान करते हुए सतत

Copyright © 2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution **4.0 International License (CC BY-NC 4.0)**

और समावेशी विकास सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक समय की मांग को ध्यान में रखते हुए नवाचार(Innovation), दक्षता(Efficiency) और समावेशिता(Inclusiveness) पर जोर देने से नीतियों को तैयार करने और लागू करने के तरीके में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। सार्वजनिक नीतियों में सबसे प्रमुख रुझानों में से एक है डिजिटल गवर्नेंस का उदय देखा जा सकता है। डिजिटल इंडिया, आधारकार्ड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे अभियानों के साथ सरकार सेवाओं की डिलीवरी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का उपयोग कर रही है। आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) ने लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाकर रिसाव और भ्रष्टाचार को कम किया है। हालांकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतराल एक बड़ी बाधा बना हुआ है। डिजिटल गवर्नेंस को सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए इस खाई को पाटना अत्यंत आवश्यक है।

परिणाम-उन्मुख शासन की ओर बढ़ना एक और उभरता हुआ रुझान शाबित हो सकता है। केवल वित्तीय इनपुट पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अब नीतियों का मूल्यांकन मापने योग्य परिणामों के आधार पर किया जा रहा है। नीति आयोग के राज्य रैंकिंग और आकांक्षी जिला कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति का आकलन करने के लिए प्रदर्शन मेट्रिक्स पेश किए हैं। यह दृष्टिकोण जवाबदेही को बढ़ावा देता है तथा राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहित करता है और संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करता है। (नीति आयोग, 2018, प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार)। भारत में सार्वजनिक नीतियों में स्थिरता एक प्रमुख मुद्दा बन गई है जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्रमोशन के लिए फेम योजना और जल संरक्षण प्रयासों जैसे जल शक्ति अभियान जैसी पहलों को जन्म दिया है। ये नीतियां न केवल पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करती हैं बल्कि हरित नौकरियों और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के अवसर भी पैदा करती हैं।(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 2024, प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार)।

व्यवहारिक अर्थशास्त्र भारत में सार्वजनिक नीति डिजाइन को तेजी से प्रभावित कर रहा है। नज थ्योरी, स्वच्छ भारत अभियान, एलपीजी सब्सिडी के लिए गिव इट अप अभियान, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी नीतियों ने सामाजिक संदेश और प्रोत्साहनों का उपयोग करके नागरिकों के व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ये पहल दिखाती हैं कि कैसे व्यवहारिक अंतर्दृष्टि नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने और समाज को बदलने में प्रभावशाली साबित हो सकती हैं। नज थ्योरी (Nudge Theory) व्यवहारिक अर्थशास्त्र (Behavioural Economics) का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर (Richard Thaler) और कैस सनस्टीन (Cass Sunstein) ने विकसित किया। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि कैसे छोटे-छोटे "नज" यानी हल्के संकेत, सुझाव या प्रोत्साहन देकर बिना लोगो की चुनाव की स्वतंत्रता को बाधित किए, लोगों के निर्णयों और व्यवहार को बदला जा सकता है।

विकेंद्रीकृत और सहभागी शासन पर बढ़ता जोर एक और महत्वपूर्ण रुझान है। माईगव जैसे प्लेटफॉर्म और सामाजिक ऑडिट के कार्यान्वयन ने नागरिकों को नीतिगत निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेने और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करने में सक्षम बनाया है। यह निचले स्तर से ऊपर तक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि नीतियां जमीनी स्तर की जरूरतों

को प्रतिबिंबित करती हैं जिससे सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास और जवाबदेही बढ़ती है। यह नागरिक-केंद्रित मंच लोगों को सरकार से जुड़ने और सुशासन में योगदान करने का अधिकार देता है। MyGov को भारत सरकार के नागरिक सहभागिता मंच के रूप में स्थापित किया गया है जो नीति निर्माण के लिए नागरिकों से जुड़ने के लिए कई सरकारी निकायों/मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है और जनहित और कल्याण के मुद्दों/विषयों पर लोगों की राय लेता है। 26 जुलाई 2014 को लॉन्च होने के बाद से, MyGov के 3 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। लगभग सभी सरकारी विभाग अपने नागरिक सहभागिता गतिविधियों, नीति निर्माण के लिए परामर्श और विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नागरिकों को जानकारी प्रसारित करने के लिए MyGov मंच का लाभ उठाते हैं। MyGov सोशल मीडिया-ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पर सबसे सक्रिय प्रोफाइल में से एक है जिसका यूजरनेम @MyGovIndia है। MyGov की Koo, Sharechat, Chingari, Roposo, Bolo Indya और Mitron जैसे कई भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महत्वपूर्ण उपस्थिति है। MyGov ने इंटरनेट, मोबाइल ऐप, IVRS, SMS और आउटबाउंड डायलिंग (OBD) तकनीकों का अभिनव उपयोग करके चर्चा, कार्य, मतदान, सर्वेक्षण, ब्लॉग, वार्ता, प्रतिज्ञा, प्रश्नोत्तरी और ऑन-ग्राउंड गतिविधियों जैसी कई सहभागिता पद्धतियों को अपनाया है। MyGov ने 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य उदाहरण भी लॉन्च किए हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड, गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मिजोरम, राजस्थान, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ शामिल हैं। (नेशनल इनफार्मेशन सेंटर, भारत सरकार, 2014)

भारत में शहरी और ग्रामीण विकास नीतियों के बीच एक अभिसरण भी देखा जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन जैसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करते हैं तथा पारंपरिक आजीविका को संरक्षित रखते हैं। रुर्बन मिशन दरअसल केन्द्र प्रायोजित एक प्रमुख योजना है। इस मिशन में धनराशि या वित्त से जुड़े दो घटक हैं: (1) विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य क्षेत्र/प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों, सीएसआर कोष के जरिए रूपांतरित धनराशि (2) कम पड़ रही अत्यंत आवश्यक धनराशि का इंतजाम (सीजीएफ)। इसमें गैर-जनजातीय क्लस्टरों के लिए प्रति क्लस्टर 30 करोड़ रुपये तक और जनजातीय एवं पहाड़ी राज्यों वाले क्लस्टरों के लिए प्रति क्लस्टर 15 करोड़ रुपये तक के सीजीएफ का प्रावधान किया गया है। मौजूदा समय में अब तक जारी की गई केन्द्रीय हिस्सेदारी वाली कुल धनराशि 1,842।97 करोड़ रुपये है। 288 आईसीएपी में 28,075 करोड़ रुपये के कुल निवेश को मंजूरी दी गई है। विभिन्न योजनाओं से रूपांतरित धनराशि 21,194 करोड़ रुपये और 6882 करोड़ रुपये है। इनमें से कुल व्यय 30 नवम्बर, 2019 तक 6,689 करोड़ रुपये का हुआ जिसमें से 5619 करोड़ रुपये रूपांतरित धनराशि के रूप में थे जबकि 1071 करोड़ रुपये सीजीएफ के तहत थे। इसके तहत जारी की जा रही सीजीएफ धनराशि के 31 मार्च, 2020 तक बढ़कर 1,200 करोड़ रुपये का लक्ष्य पार कर लेने की आशा है। (प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो दिल्ली, भारत सरकार, 2020)।

स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी पहल प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के माध्यम से शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। ये प्रयास शहरीकरण के दबावों और ग्रामीण विकास के बीच संतुलन स्थापित करके समग्र विकास को बढ़ावा देते हैं। डेटा-आधारित नीति निर्माण भारत में शासन को बदल रहा है। बड़ी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुदृढ़ कर रहा है। उदाहरण के लिए, COVID-19 महामारी के दौरान वास्तविक समय में डेटा निगरानी ने संसाधनों के कुशल आवंटन और संकट प्रबंधन को संभव बनाया। इसी तरह के अनुप्रयोग शहरी योजना और मनरेगा जैसे कल्याण कार्यक्रमों में उपयोग किए जा रहे हैं। डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि नीतियां अनुकूलनीय, लक्षित और बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हों। लैंगिक-उत्तरदायी और समावेशी नीतियां भारत के सार्वजनिक नीति परिदृश्य में प्रमुखता प्राप्त कर रही हैं। लैंगिक-उत्तरदायी बजटिंग, महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिए के समुदायों के लिए लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार की समानता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये नीतियां ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और एक अधिक समावेशी समाज बनाने का प्रयास करती हैं।

भारत की सार्वजनिक नीतियां वैश्विक रूपरेखाओं और मानकों जैसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के साथ तेजी से मेल खा रही हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह मेलजोल भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण की खाई को पाटने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र बन गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत राजमार्गों से लेकर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के डिजिटलीकरण तक, PPP मॉडल सार्वजनिक संसाधनों को निजी क्षेत्र के नवाचार के साथ जोड़ रहा हैं। हालांकि इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण में पारदर्शिता और समान लाभ सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।

इन आशाजनक रुझानों के बावजूद सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में कई चुनौतियां बनी हुई हैं। डिजिटल अंतराल, निचले स्तर के शासन में संस्थागत क्षमता की कमी और क्षेत्रीय असमानता प्रभावी नीति कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं। विकास और स्थिरता, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, और कल्याण और बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाना उचित रणनीतियों की आवश्यकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना, कम सेवा वाले क्षेत्रों में निवेश करना और बहु-हितधारक सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक कदम हैं। भारत में सार्वजनिक नीतियों में उभरते रुझान समकालीन चुनौतियों के प्रति देश की अनुकूलता और एक सतत और समावेशी भविष्य की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। प्रौद्योगिकी, वैश्विक मानदंडों और अभिनव दृष्टिकोणों को एकीकृत करके ये नीतियां शासन को बदलने और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करती हैं। जैसे-जैसे भारत विकास की ओर अग्रसर है ये रुझान इसे शासन और विकास में एक वैश्विक नेता के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

भारत में सार्वजनिक नीतियों का विकास - भारत में सार्वजनिक नीतियों के विकास पर कई विद्वानों ने ऐतिहासिक, सामाजिक, और राजनीतिक संदर्भों का विश्लेषण किया है। इनमें मोरिस जोन्स, रजनी कोठारी, अटल कोहली, और अन्य प्रमुख विद्वानों के दृष्टिकोण शामिल हैं जो भारतीय नीतियों के विकास और उनकी चुनौतियों को समझने में मदद करते हैं। मोरिस जोन्स(1967) ने भारतीय लोकतंत्र को "तीन भाषाओं की राजनीति" (Politics of Three Languages) के रूप में वर्णित किया। उनका मानना है कि सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में पारंपरिक, आधुनिक, और औपनिवेशिक तत्व आपस में घुलमिल गए हैं। यह मिश्रण नीति-निर्माण के दौरान विविध हितों और आवश्यकताओं को संतुलित करने की चुनौती प्रस्तुत करता है। इसमें उन्होंने भारतीय राजनीति के तीन प्रमुख प्रतिमानों को चिन्हित किया, जिन्हें उन्होंने "भाषाएं" कहा। इन भाषाओं के माध्यम से भारतीय राजनीति में विभिन्न विचारधाराओं, परंपराओं और प्रवृत्तियों के समन्वय को समझा जा सकता है। आधुनिक भाषा पश्चिमी लोकतांत्रिक विचारों और संस्थानों को दर्शाती है। इसमें संवैधानिकता, कानून का शासन, मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और पश्चिमी उदार लोकतंत्र की विचारधाराएं शामिल हैं। यह भाषा आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर्ग, नौकरशाही और शहरी मध्यम वर्ग में प्रचलित है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली, और न्यायपालिका को लिया जा सकता है। परंपरागत भाषा भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को दर्शाती है। इसमें जाति व्यवस्था, धर्म आधारित समाज, और पारंपरिक मूल्य शामिल हैं। यह ग्रामीण भारत और पारंपरिक समाज के लोगों में अधिक प्रचलित है। ग्राम पंचायतें, धार्मिक संगठन, और स्थानीय परंपराओं के अनुसार राजनीतिक गतिविधियां इसके तहत आते है। लोकप्रिय भाषा आम जनता की आकांक्षाओं, भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करती है। इसमें करिश्माई नेतृत्व, जनभावनाओं का सम्मान, और जनहितकारी नीतियों का जोर होता है।

यह भाषा अक्सर राजनीति में सामूहिक आंदोलनों और बड़े पैमाने पर जनभागीदारी को बढ़ावा देती है। राजनीतिक रैलियां, किसान आंदोलन, और जाति-आधारित जनसंगठन इसके तहत रखे जा सकते है। भारतीय राजनीति में इन तीन भाषाओं का सह-अस्तित्व है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत ने आधुनिक संस्थानों को अपनाया (आधुनिक भाषा), लेकिन परंपराओं (परंपरागत भाषा) और जनता की भावनाओं (लोकप्रिय भाषा) को भी महत्व दिया। यह समन्वय भारत की लोकतांत्रिक स्थिरता और विविधता को बनाए रखने में सहायक रहा है (जोंस 1967)।

रजनी कोठारी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, "पॉलिटिक्स इन इंडिया" में भारत की राजनीतिक संरचना और नीतिगत प्रक्रियाओं की विस्तार से व्याख्या की है। उन्होंने भारतीय नीतियों में कांग्रेस प्रणाली की भूमिका पर जोर दिया और बताया कि कैसे यह प्रणाली सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक रही। उनके अनुसार भारतीय नीतियां सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं थी बल्कि एक व्यापक गठबंधन के रूप में कार्य कर रही थी जिसमें विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक गुट समाहित थे। कांग्रेस ने विपक्षी दलों के कमजोर होने के बावजूद एक समावेशी प्रणाली बनाई जहां विभिन्न विचारधाराएं पार्टी के अंदर ही स्थान पाती थीं। कोठारी ने जाति, वर्ग, धर्म और भाषा जैसी सामाजिक संरचनाओं के भारतीय राजनीति पर प्रभाव का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे ये सामाजिक तत्व न केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं बल्कि लोकतंत्र को भी मजबूती प्रदान करते हैं। कोठारी ने राजनीतिक विकास और स्थिरता के बीच

संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक आंदोलनों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र ने खुद को टिकाऊ साबित किया है। (कोठारी, 1967)।

अतुल कोहली ने भारत की नीतियों को औद्योगिक विकास और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में देखा। उन्होंने आर्थिक सुधारों और राज्य के हस्तक्षेप की भूमिका का अध्ययन किया। उनके अनुसार भारतीय राज्य का विकास एक "संघर्षशील लोकतंत्र" (Struggling Democracy) के रूप में हुआ, जहाँ नीतियों ने सामाजिक और आर्थिक समानता को प्रोत्साहित किया। कोहली ने यह तर्क दिया कि भारतीय राज्य ने लोकतंत्र को स्थिर बनाए रखने के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने की कोशिश की है। भूमि सुधार, आरक्षण नीति, और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को इस संघर्ष का हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि इन प्रयासों में सीमाएं भी रहीं जो असमानताओं को पूरी तरह समाप्त करने में असफल रही। उन्होंने देखा कि भारतीय नीतियों ने गरीबी घटाने के लिए कई कदम उठाए जैसे कि हरित क्रांति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए योजनाएं। लेकिन कोहली के अनुसार इन नीतियों का प्रभाव स्थायी नहीं रहा क्योंकि वितरण की व्यवस्था और नीतिगत क्रियान्वयन में कई खामियां थीं। कोहली ने यह भी बताया कि भारतीय लोकतंत्र में शक्ति और संसाधनों के वितरण को लेकर हमेशा संघर्ष रहा है। यह संघर्ष कभी-कभी संस्थानों के भीतर देखा गया (जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच) और कभी सामाजिक आंदोलनों के रूप में प्रकट हुआ (जैसे दलित और महिला आंदोलनों में)। कोहली ने आर्थिक उदारीकरण की प्रशंसा करते हुए यह भी चेतावनी दी कि अगर राज्य केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा और सामाजिक कल्याण को नजरअंदाज करेगा तो यह लोकतंत्र के लिए चुनौती बन सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आर्थिक सुधारों को इस तरह लागू किया जाना चाहिए जिससे समाज के वंचित वर्ग भी लाभान्वित हों। कोहली के अनुसार आर्थिक विकास और लोकतंत्र के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भारत की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि वह विकास को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ सके (कोहली, 2010)।

आशीष नंदी ने भारतीय नीतियों में सांस्कृतिक और सामाजिक तत्वों की भूमिका पर बल दिया। उनके अनुसार भारतीय नीतियों को केवल आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं के संदर्भ में नहीं बल्कि उनके सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में भी समझना आवश्यक है। भारत में विकास और नीतियों को अक्सर पश्चिमी आधुनिकता और तर्कसंगतता के आधार पर परिभाषित किया जाता है जो भारत की विविध सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं को पर्याप्त रूप से नहीं समझते। नंदी का मानना है कि भारतीय समाज को अपनी जड़ों, परंपराओं और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों से जोड़ते हुए नीतियां बनानी चाहिए, (नंदी,1983)।

पार्थ चटर्जी ने नीतियों में लोकतांत्रिक शासन और औपनिवेशिक शासन की निरंतरता को समझाया। चटर्जी के अनुसार भारतीय राज्य की संस्थाएं और नीतियां ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत विकसित हुईं और उनका प्रभाव आज भी भारतीय लोकतंत्र में देखा जाता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि भारतीय प्रशासनिक तंत्र, न्यायिक प्रणाली, और अन्य सरकारी संस्थाएं औपनिवेशिक शासन से विरासत में मिली हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राज्य की कुछ नीतियां और विचारधाराएं जो सामान्य जनता के जीवन पर प्रभाव डालती हैं वह भी औपनिवेशिक शासन से उपजी हैं जैसे भेदभावपूर्ण नीतियां, सामाजिक नियंत्रण और राज्य की शक्ति को केंद्रीकरण के रूप में देखना। चटर्जी ने बताया कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव, प्रतिनिधित्व,

और नागरिक अधिकारों की अवधारणाएं, जो औपनिवेशिक शासन से पहले ब्रिटिश शासन में अस्तित्व में आई थीं भारतीय संदर्भ में लागू की गईं। हालांकि लोकतंत्र ने समाज में समानता और अधिकारों का वादा किया लेकिन औपनिवेशिक शासन की मानसिकता और व्यवस्था के तत्व इस लोकतंत्र में प्रवेश कर गए। (चटर्जी, 1993)।

जीन ड्रेज़ और अमर्त्य सेन ने सार्वजनिक नीतियों में मानव विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया। अमर्त्य सेन ने मानव विकास की परिभाषा को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने इसे मानव के समग्र कल्याण और स्वतंत्रता से जोड़ा। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत "Capability Approach" (संपन्नता दृष्टिकोण) है जिसमें उन्होंने यह बताया कि किसी समाज की समृद्धि की माप केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या आय के स्तर से नहीं की जा सकती बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी क्षमताओं और स्वतंत्रताओं का कितनी अच्छी तरह उपयोग कर पा रहे हैं। सेन के अनुसार विकास का उद्देश्य केवल लोगों की आय बढ़ाना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वे अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच आदि। ड्रेज़ और सेन दोनों ने यह सुझाव दिया कि सार्वजनिक नीतियों का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ बढ़ाना नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना होना चाहिए। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और रोजगार जैसी कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि समाज के सभी वर्गों को बराबरी का अवसर मिल सके। उनके अनुसार विकासशील देशों में सार्वजनिक नीतियाँ और योजनाएँ तभी सफल हो सकती हैं जब उनमें पारदर्शिता हो और वे जनता की भागीदारी से तैयार की जाएं। उन्होंने यह सुझाव दिया कि यदि सरकार के निर्णय में नागरिकों की भागीदारी और निगरानी सुनिश्चित की जाती है तो नीतियाँ ज्यादा प्रभावी और न्यायपूर्ण होंगी(सेन 1999 और सेन और ड्रेज, 1996)।

भारत में सार्वजनिक नीतियों का विकास औपनिवेशिक शासन से शुरू होकर आजादी के बाद योजनाबद्ध विकास तक विस्तारित है। 1950 और 1960 के दशक में सार्वजनिक योजनाएं समाजवादी मॉडल पर आधारित थीं जबकि 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण ने नीतिगत दृष्टिकोण को बदल दिया। वर्तमान में नीतियों का जोर समावेशिता, डेटा आधारित निर्णय-निर्माण, और सतत विकास पर अधिक निर्भर है। जैसे नई शिक्षा नीति (2020), डिजिटल इंडिया, और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित नीतियां इसका उचित उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन विद्वानों के विचार भारतीय नीतियों की बहुआयामी प्रकृति और उनके विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत की सार्वजनिक नीतियां हमेशा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती रही हैं।

सार्वजनित नीतिया और चुनौतिया - ड्रोर(2017) का मानना है कि नीति निर्माण प्रक्रिया अक्सर अति-सिद्धांतवाद और व्यवहारिकता की कमी से ग्रस्त होती है। यह विशेष रूप से भारत जैसे देशों में अक्सर देखा जाता है जहाँ विविध सामाजिक वास्तविकताएँ अनुकूलनशील दृष्टिकोण की माँग करती हैं। वे साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की कमी की आलोचना करते हैं और स्थानीय संदर्भों को वैश्विक ढाँचों में शामिल करने का आह्वान करते हैं। एंडरसन (1979) नीति चरणों की खंडित प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। उनके अनुसार नीति विफलताएँ अक्सर निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के बीच समन्वय की कमी के कारण होती हैं। भारत में यह खराब कार्यान्वित योजनाओं जैसे शिक्षा का अधिकार (RTE) में स्पष्ट है जो वित्तपोषण और प्रशासनिक अक्षमताओं से जूझता है। कपूर और मेहता (2018) के अनुसार भारत की शासन प्रणालियाँ

कमजोर संस्थागत ढाँचों, अत्यधिक केंद्रीकरण, और नौकरशाही जड़ता से ग्रस्त हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भूमि अधिग्रहण और अंतर-विभागीय समन्वय में अक्षमताओं के कारण विलंब का सामना करती है। बर्धन (2017) भ्रष्टाचार को एक प्रणालीगत दोष मानते हैं जो सार्वजनिक नीतियों की प्रभावशीलता को कमजोर करता है। उनका तर्क है कि MGNREGA जैसे कल्याणकारी योजनाएँ जबकि परिवर्तनकारी हैं, अक्सर कमजोर निगरानी तंत्र और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण धन के दुरुपयोग का सामना करती हैं। सेन(1999) जोर देते हैं कि भारत में सार्वजनिक नीतियाँ अक्सर सामाजिक न्याय पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता देती हैं जिससे बहिष्करणीय विकास होता है। वे स्पेशल इकोनोमिक जोंस(एस इ जेड) नीतियों जैसी पहलों की आलोचना करते हैं जो ग्रामीण समुदायों को हाशिये पर ले जाती हैं और भूमि अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। उनका तर्क है कि सच्चा विकास स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना चाहिए न कि उन्हें प्रतिबंधित करना। नय्यर (2019) भारत में नीति कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असमानताओं की आलोचना करते है तथा यह तर्क देते है कि उत्तर-पूर्वी और जनजातीय क्षेत्रों को उच्च GDP वृद्धि के बावजूद उपेक्षित किया गया है। इस प्रकार की नीतियाँ अक्सर शहरी-केंद्रित विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं जिससे ग्रामीण आबादी की उपेक्षा होती है।

निष्कर्ष एवमं सुझाव - भारत में सार्वजनिक नीतियों का निर्माण भारत की स्वतंत्रता से पहले से होता आया है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी सार्वजनिक नीतियों का निर्माण हुआ करता था लेकिन उन नीतियों का मूलभूत उद्देश्य भारत से धन, संपत्ति आदि मूल्यवान वस्तुओ की लूट पर आधारित होता था तथा उन सभी नीतियों का उद्देश्य अनेक प्रकार से इंग्लैंड सरकार को आर्थिक लाभ पहुचाना होता था। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद से भारत की सार्वजनिक नीतियों का उद्देश्य बदला तथा वह समाज के उत्थान और विकास पर केन्द्रित हुई। सुरवाती दौर में सार्वजनिक नीतिया सामाजवाद से प्रभावित रही। समाज के वंचित तबको को सार्जनिक निर्णयों में भागीदार बनाना, नागरिको को निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित करना तथा देश की नीतियों को समावेशी बनाये जाने पर जोर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे देश की हुकूमत ने यह अहसास किया किया कि देश को बाजारवाद से जोड़ना अनिवार्य है। इस जरूरत को ध्यान में रखकर उदारीकरण की अर्थव्यवस्था को अपना लिया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्र, सामाजिक सहभागिता, सामाजिक न्याय तथा प्रतिनिधित्व आधारित नीतियों पर अब अधिक ध्यान दिया जाने लगा। यह व्यवस्था पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित हो गयी जो आज तक जारी है। देश के नीतियों को ग्रामीण इलाको में लागू करना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। नीतिया केवल बन जाने से काम नहीं चलेगा उनके सही और उचित लागू करने की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। वर्तमान मोदी सरकार ने इस और अनेक प्रयास किये है लेकीन अभी मंजिल बहुत दूर है। उम्मीद की जा सकती है कि भारत को 2047 में एक विकसित देश के रूप में जब देखा जाएगा तो जरूर सार्जनिक नीतियों से जुडी तमाम समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Chatterjee, P. (1993). The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. *Princeton UP*.
2. JONES, W. H. M. (1967). The Government and Politics of India.. Hutchinson & Company.

3. Colonialism, R. O. S. U. The Intimate Enemy: Loss And Recovery of Self Under Colonialism (Oxford India Paperbacks)
4. Nandy, A. (1987). Traditions, tyranny, and utopias: Essays in the politics of awareness.
5. Kohli, A. (2010). Democracy and development in India: From socialism to pro-business. *OUP Catalogue*.
6. Dreze, J., & Sen, A. (1996). *India economic development and social opportunity*. Oxford University Press.
7. Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf, INC.
8. Dror, Y. (2017). *Public policy making re-examined*. Routledge.
9. Anderson, James. E, (1979). Public Policy making. Holt, Rinehart and Winston.
10. Kapur, D., Mehta, P. B., & Vaishnav, M. (Eds.). (2018). *Rethinking public institutions in India*. Oxford University Press.
11. Bardhan, P. (2017). Corruption and development: a review of issues. *Political corruption*.
12. Nayyar, D. (2019). *Resurgent Asia: Diversity in Development* . Oxford University Press.
13. MyGov: An Overview | MyGov.in Online URL portal.
14. Honoured, C. O. (2020). Press Information Bureau Government of India.
15. Scheme, Rurban Mission (2020). Press Information Bureau. Ministry of Rural Development, Government of India (20th February 2020, 6:44PM).
16. Scheme, Champions of Change (2018). Press Information Bureau. Niti Ayog, Government of India (28th March 2018, 8:51PM).
17. Scheme, Climate action and carbon neutrality (2024). Press information bureau, Bhopal. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India (1st August 2024, 1:04PM).